कुणाल शर्मा, सचिव. उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक / 2 अप्रैल,2013 विषय:— वित्तीय वर्ष 2013-14 में सहकारिता विमाग के अन्तर्गत सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विमिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय.

वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या:-284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तर-2 में उल्लिखित विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹52,80,000/-(रूपये बावन लाख अस्सी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।

व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपन्न बी०एम०१३ पर 10 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)

2— उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के अनुदान संख्या—18 के लेखाशीर्षक 2425—सहकारिता आयोजनेत्तर, 001—निदेशन तथा प्रशासन, 05—सहकारिता न्यायाधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा:—

(धनराशि हजार रू० में)

		(यगराहित हजार क
मानक मद का मद	नाम	स्वीकृत घनराशि
01- वेतन		2000
02- मजदूरी		75
03- महंगाई भत्ता		1800
04- यात्रा व्यय		10
05— स्थानान्तरण यात्रा व्यय		10
06- अन्य भत्ते		500
09— विद्युत देय		10
10- जलकर/जलप्रभार		10
11— लेखन सामाग्री व फार्मों की छपाई		10
13- टेलीफोन पर व्यय		50
15— गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद		80
16— व्यवसायिक तथा विशेष सेव	ाओं के लिये भुगतान	350
17- किराया, उपशुल्क और कर-	-स्वामित्व	275
27- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		50
45— अवकाश यात्रा व्यय		50
योग		5280

(रूपये बादन लाख अस्सी हजार मात्र)

3— ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय, (कुणाल शर्मा) सचिव।

संख्या:- 🔏 ५ 9(1) / XIV-1 / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. वित्त अनुभाग-4/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

🖫 प्रभारी, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

- 5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7. गार्ड फाईल।